आलोक मेहता

# 'हम न बदले, तुम न बदले'

## गुरु गोलवलकर ही समान नागरिक संहिता के पक्ष में नहीं थे

लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेतृत्व के स्वरों में अधिक मिठास आ गई लगती है। संघ की प्रतिनिधि सभा ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार को पुनः सत्ता में लाने का वरदान दे दिया। संघ ने राजग सरकार की पांच सालाना उपलब्धियों का बखान करते हुए अपने स्वयंसेवकों को मंदिर-मस्जिद के मुद्दों के बजाय विकास-गान गांव-गांव तक पहुंचाने का मार्गदर्शन दिया है। जयपुर बैठक से उन नेताओं, राजनीतिक विश्लेषकों तथा पत्रकारों को शायद थोड़ा झटका लगा होगा जो पिछले पांच वर्षों से संघ, विश्व हिंदू परिषद, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ आदि के सरकार के साथ टकराव की तथाकथित स्थितियों को जोर-शोर से उछालते थे। लेकिन मेरे जैसे संवाददातानुमा पत्रकार को कतई आश्चर्य नहीं हुआ। इसी संदर्भ में भी मैं यदा-कदा इस बात को उठाता रहा हूं कि संघ और भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं के बीच गहरी समझ-बूझ है और विरोधियों का मजा लेने के लिए दिल्ली दरबार से अयोध्या तक की घेराबंदी का नाटक चलता रहता है। भाजपा ने यह कला भी कांग्रेस से ही सीखी है। इंदिरा गांधी तो सोची-समझी रणनीति के तहत डॉ. शंकरदयाल शर्मा और प्रकाश चंद्र सेठी जैसे विश्वस्त सहयोगियों को दल से बाहर भिजवाकर अपना विरोध करवा लेती थीं। फिर भाजपा नेताओं ने सदा यह स्वीकारा कि उन्हें संघ का 'स्वयंसेवक' और हिंदू कहलाने का गौरव है। समस्या केवल व्यक्तित्वों के अहम को लेकर आती रही है। दूसरी उलझन यह रही कि लोग संगठन और सत्ता से जुड़े 'स्वयंसेवकों' को डॉ. हेडगेवार या गुरु गोलवलकर द्वारा निर्धारित नैतिक मूल्यों और राजनीतिक आदर्शों के मानदंडों पर तोलने की कोशिश करते रहे। इस संदर्भ में संघ के पूर्व सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर ने 2 दिसंबर, 1970 को धारा नगर में अपने स्वयंसेवकों के बीच कह दिया था, 'राज सत्ता के कारण हमारा दिमाग ठीक रहेगा, बुद्धि ठीक रहेगी, इसका विश्वास कहां है? राज सत्ता प्राप्त होने पर अनेक अच्छे-अच्छे लोग भी विकृति से भर गए। यह सत्ता का प्रभाव है। उसका परिणाम होता ही है। मद रहता है उसका। फिर अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए भले-बुरे सभी प्रकार के मार्गों का अवलंबन करने की इच्छा हो जाती है। अतः अगर सत्ता मिल गई तो वह इन सब प्रकार के दुर्गुणों की शिकार बनकर राष्ट्र के लिए संकट नहीं बनेगी, ऐसा विश्वास कैसे और कहां से आएगा?'

> **राजग की छतरी में होनेवाले हर सुराख के साथ भाजपा के झंडे का रंग अधिक गहरा होता रहा। मामला शिक्षा का हो या कश्मीर का, सरकार में रहते हुए भाजपाई नेताओं ने वही किया जो संघ का लक्ष्य रहा है।**

भाजपा में दूसरी-तीसरी पंक्ति के कई ऐसे नेता होंगे जो सीधे गुरु गोलवलकर के संपर्क में कभी न आए हों, बालासाहेब देवरस के विचारों की छाया उन पर पड़ी हो और उसके बाद संघ के उदारवादी नेतृत्व से उन्हें राजनीति में जमने में अधिक सुविधा हो गई हो। केवल अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी उस श्रेणी में कहे जा सकते हैं जिन पर गुरु गोलवलकर का सर्वाधिक असर रहा। यही कारण है कि हाल के वर्षों में संघ से जुड़े नेता निर्देश देने के बजाय इन्हीं नेताओं से सलाह लेते-देते रहे। फिर उन्हें भाजपा नेताओं से असली शिकायत क्यों रहती? राजग की छतरी में होने वाले हर सुराख के साथ भाजपा के झंडे का रंग अधिक गहरा होता रहा। मामला शिक्षा का हो या कश्मीर का, सरकार में रहते हुए भाजपाई नेताओं ने वही किया जो संघ का लक्ष्य रहा है। पिछले दिनों समान नागरिक संहिता का विवाद जोरों से उछला और संघ, विहिप तथा कुछ भाजपा नेता इसके पक्ष में बयानबाजी भी करते रहे। उन्हें शायद पता ही नहीं है कि उनकी मातृ संस्था के आदर्श गुरु गोलवलकर ने 20 अगस्त, 1972 को अपने विचारों से जुड़े अखबार मदरलैंड को एक इंटरव्यू में कह दिया था, 'राष्ट्रीयता की भावना के पोषण के लिए मैं समान नागरिक संहिता को आवश्यक नहीं मानता। इससे बहुतों को आश्चर्य हो सकता है। लेकिन यह मेरा मत है। एकता के लिए एकविधता नहीं अपितु समरसता आवश्यक है।' उनसे पूछा गया कि 'संविधान के निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया है कि राज्य समान नागरिक संहिता के लिए प्रयत्न करेगा।' गुरुजी ने उत्तर दिया, 'संविधान में कोई बात होने मात्र से ही वांछनीय नहीं बन जाती। फिर अपना संविधान कुछ विदेशी संविधानों के जोड़-तोड़ से बना है। यह न तो भारतीय जीवन दृष्टिकोण से रचा गया है और न उस पर आधारित है। मुस्लिम प्रथाओं के प्रति आपकी आपत्ति यदि मानवीय कल्याण के व्यापक आधार पर हो तब तो वह उचित है। ऐसे मामलों में सुधारवादी दृष्टिकोण ठीक है। परंतु यांत्रिक ढंग से कानूनों जैसे बाह्यवर्ती उपचारों द्वारा सबमें समानता लाने का दृष्टिकोण रखना ठीक नहीं होगा। मुसलमान चाहें तो स्वयं अपने पुराने नियम-कानूनों में सुधार करें। मेरा मत है कि एकविधता राष्ट्र के विनाश की सूचना है।'

इस तरह के स्पष्ट विचारों से प्रभावित रहे वाजपेयी यदि अपने सत्ता काल में समान नागरिक संहिता का कानून नहीं बना सके तो संघ के असली नेताओं को कष्ट क्यों होना चाहिए? इसी तरह अयोध्या विवाद तथा कुछ अन्य मुद्दों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार ब्रजेश मिश्र से नाराजगी की बातें भी पिछले वर्षों के दौरान उछलती रहीं। लेकिन संघ की पृष्ठभूमि जानने वाले क्या यह तथ्य भूला सकते हैं कि 50 वर्ष पहले कांग्रेस शासन में गुरु गोलवलकर को जेल से रिहा करवाने में ब्रजेश मिश्र के पिता मध्य प्रदेश के तत्कालीन गृह मंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? संघ सदैव भारत को परमाणु शक्ति-संपन्न देखना चाहता था। वाजपेयी सरकार ने परमाणु परीक्षणों और हथियारों में भारत को अग्रणी बना दिया। इतिहास की पाठ्यपुस्तकें बदलवा दीं। सर्व शिक्षा अभियान के जरिये 576 जिलों तक नैतिक तथा सांस्कृतिक शिक्षा का कार्यक्रम बढ़ा दिया। गोवंश रक्षा अभियान के साथ भारत विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। पांच साल में 11,276 करोड़ रुपया राज्य सरकारों को बांटकर 31 हजार गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बढ़ने से ईसाई मिशनरी संस्थाओं की तरह संघ या विहिप से जुड़ी स्वयंसेवी संस्थाओं को अपने कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए करोड़ों रुपयों का चंदा मिल सका। दूसरी तरफ आतंकवाद निरोधक कानून के मार्फत खाड़ी के मुस्लिम देशों से भारत में आ रहे धन पर अंकुश लगा। गुजरात में भीषण दंगों के बाद भी नरेंद्र मोदी को सत्ता से नहीं हटाकर केंद्र से पूरा समर्थन दिया गया। संन्यासिन उमा भारती तक को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवा दिया। अयोध्या-विवाद को इस हद तक मोड़ दिया कि अल्पसंख्यक नेता भी वार्ता की मेज पर बैठने के लिए तैयार दिखने लगे। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ संवाद के जरिये सीमा पर आवागमन अधिक सुगम बना दिया। आखिरकार, इस सबके बाद संघ के नेता किस मुंह से भाजपा का विरोध कर सकते हैं? ●